



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 13 अक्टूबर, 2006/21 आश्विन, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 13 अक्टूबर, 2006

संख्या एल० एल० आर०-डी०(६)-23/2006.—हिमाचल प्रदेश के राजपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11-10-2006 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 19) को

वर्ष 2006 के अधिनियम संख्यांक 22 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2006

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 11 अक्टूबर, 2006 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम संक्षिप्त नाम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। और प्रारम्भ।

(2) यह 4 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1977 का 12

2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें धारा 67 का इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 67 के स्थान पर निम्नलिखित रखा प्रतिस्थापन।
जाएगा, अर्थात्:-

"67. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.—(1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण होगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) अध्यक्ष; और

(ख) ऐसे अन्य सदस्य, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं,

जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, यदि समीचीन समझे, किसी भी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोनों, नियुक्त कर सकेगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन होगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

- (4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य किसी भी प्रकार के वेतन के हकदार नहीं होंगे परन्तु ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे विहित किए जाएं।
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसे उक्त प्राधिकरण द्वारा बनाए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।”।

धारा 68 का
प्रतिस्थापन। अर्थात्:-

3. मूल अधिनियम की धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

“68. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का निगमन.-

- (1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जब तक उत्सादित न हो, एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।
- (2) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 67 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से उत्सादित कर सकेगी, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए और उक्त प्राधिकरण तदनुसार उत्सादित हो जाएगा।
- (3) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्सादित करने की तारीख से ही ऐसी सभी सम्पत्तियां, परिसम्पत्तियां, दायित्व, निधियां, शोध्य रकमें, जो उक्त प्राधिकरण द्वारा वसूली योग्य हैं और कर्मचारी जो उसमें निहित हैं, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकरण या निगम या अभिकरण, जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करे, द्वारा वसूली योग्य होंगे और उसमें निहित हो जाएंगे।”।

2006 के
अध्यादेश
संख्यांक 3
का निरसन
और

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 22 of 2006

**THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING
(AMENDMENT) ACT, 2006**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 11TH OCTOBER, 2006)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2006.

Short title
and
commence-
ment.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 4th day of July, 2006.

2. For section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the “principal Act”), the following shall be substituted, namely:—

Substitution
of section
67.

“67. **Special Area Development Authority.**—(1) Every special area shall have Special Area Development Authority, which shall consist of—

(a) the Chairman; and

(b) such other members as the State Government may determine from time to time,

who shall be appointed by the State Government.

(2) The State Government may, if consider expedient, appoint Vice-Chairman or Chief Executive Officer or both, for any Special Area Development Authority.

- (3) The Chief Executive Officer shall be a whole time officer of the Special Area Development Authority who shall receive such salary and allowances and shall be subject to such terms and conditions as may be determined by the State Government.
- (4) The Chairman, Vice Chairman and members shall not be entitled to any salary but shall receive such allowances as may be prescribed.
- (5) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by regulations made by the said Authority.”.

Substitution
of section
68.

3. For section 68 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“68 Incorporation of Special Area Development Authority.

- (1) Every Special Area Development Authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, unless abolished, with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immovable, and to contract, and shall sue and be sued by the name specified in the notification under sub-section (1) of section 66.
- (2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, abolish the Special Area Development Authority constituted under section 67 of the Act from such date as may be specified therein and the said Authority shall stand abolished accordingly.
- (3) On and with effect from the date of abolition of the Special Area Development Authority all properties, assets, liabilities, funds, dues and staff which are realisable and vested in the said Authority shall be realisable and shall vest in such authority or corporation or agency, as the case may be, as the State Government may decide.”.

Repeal of
Ordinance
No. 3 of
2006 and
savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2006 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.